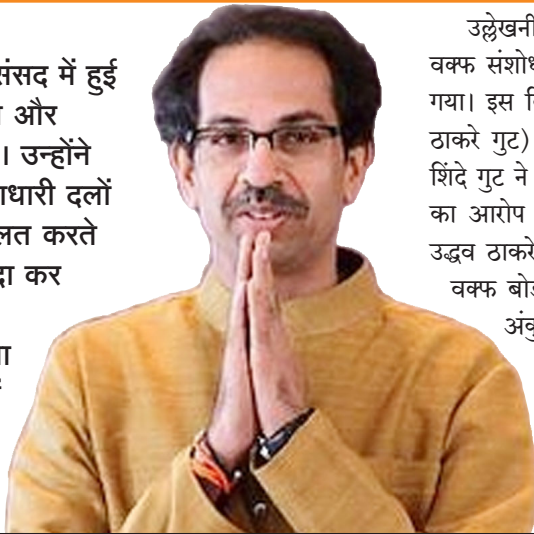


जिन्ना को भी शर्मिंदा कर देने वाले मुस्लिम समाज के पक्ष में भाषण

उद्भव ठाकरेका भाजपा पर तीखा हमला

मुंबई, ३ अप्रैल (जमीर काजी):

वक्फ संशोधन एवं सुधार विधेयक पर संसद में हुई बहस को लेकर उद्भव ठाकरे ने भाजपा और सहयोगी दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में जिस प्रकार सत्ताधारी दलों के नेताओं ने मुस्लिम समाज की वकालत करते हुए भाषण दिए, वो जिन्ना को भी शर्मिंदा कर दें। फिर सवाल यह उठता है कि यह विधेयक मुस्लिम समाज के पक्ष में है या विरोध में? यदि यह मुस्लिमों के पक्ष में है, तो इसका विरोध करने पर हम पर हिंदुत्व छोड़ने का आरोप कैसे लगाया जा सकता है?



उल्लेखनीय है कि बुधवार की रात लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक बहुमत से पारित किया गया। इस विधेयक का विरोध शिवसेना (उद्भव ठाकरे गुट) ने किया, जिसके बाद भाजपा और शिंदे गुट ने ठाकरे गुट पर हिंदुत्व से विमुख होने का आरोप लगाया। इसके जवाब में गुरुवार को उद्भव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यदि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार हो रहा है तो उस पर अंकुश लगाना चाहिए और पारदर्शिता आनी चाहिए, लेकिन संसद में जिस तरह की बातें की गईं, उससे स्पष्ट होता है कि सरकार की नज़र वक्फ की जमीनों पर है।

ठाकरे ने भाजपा की दोहरी

नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि किरन रिजिजू, जिन्होंने पहले बीफ़ खाने का समर्थन किया था, उन्होंने ही यह विधेयक पेश किया। भाजपा के खाने के दांत कुछ और, दिखाने के कुछ और हैं। उन्होंने यह भी कहा कि धारा ३७० हटाने का हमने समर्थन किया था, लेकिन कश्मीरी पंडितों को अब तक कितनी ज़मीनें वापस दी गईं, यह सरकार को पहले बताना चाहिए।

हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा उद्भव ठाकरे ने कहा, कुछ अवसरवादी और गद्दार लोग कह रहे हैं कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया है, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। बाला साहेब ठाकरे ने कभी यह नहीं कहा कि सारे मुस्लिम देशद्रोही हैं। १९९५ में उन्होंने बीकेसी में मुस्लिम

समाज को इज्तेमा करने की अनुमति दी थी। आज उसी जगह पर बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट लाया गया है - क्या यही तुम्हारा हिंदुत्व है?

अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ पर भी बोलें प्रधानमंत्री

उद्भव ठाकरे ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत पर २६% आयात शुल्क लगा दिया है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे समय में सभी मुद्दों को छोड़कर प्रधानमंत्री को इस आर्थिक संकट पर देश को जानकारी देनी चाहिए। ठाकरे ने मांग की कि सरकार को देशहित में आर्थिक नीतियों पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए।

भगवान बाबा की शिक्षाओं से समाज आत्मसम्मान के साथ कर रहा है प्रगति-पंकजा मुंडे

बीड, २ अप्रैल (प्रतिनिधि): जमीन बेचो, लेकिन शिक्षा जरूर लो - यह संदेश राष्ट्रसंत भगवान बाबा ने समाज को दिया था। उन्हीं की प्रेरणा से आज समाज हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। हम गन्ना तोड़नेवाले हैं, मेहनती हैं, लेकिन आत्मसम्मान से जीनेवाले भी हैं। आज की युवा पीढ़ी को गलत रास्तों से दूर रहकर अपने विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यह प्रेरणादायक संदेश राज्य की पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे ने यहां आयोजित एक कार्यक्रम में दिया। यह अवसर था पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्राप्त निधि से पूर्ण हुए कार्यों के लोकार्पण और नये विकास कार्यों के भूमिपूजन का, जो उत्साहपूर्ण



वातावरण में पंकजा मुंडे के हाथों संपन्न हुआ।

इस अवसर पर प्रतिष्ठान के डॉ. प्रभाकर धायतडक, आर. टी. गर्जे, डॉ. अमोल लहाने, डॉ. शिवाजी सानप, शिवरूद्रानंद महाराज, योगेश क्षीरसागर, भाजपा जिलाध्यक्ष शंकर देशमुख सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। अपने भाषण में पंकजा मुंडे ने कहा, संत भगवान बाबा प्रतिष्ठान के विभिन्न विकास कार्यों के

लोकार्पण व भूमिपूजन करते हुए मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। संत भगवान बाबा का सपना था - एक शिक्षित, प्रगतिशील और आत्मसम्मानी समाज का निर्माण। इस दिशा में थोड़ा बहुत योगदान दे पाने की संतुष्टि मुझे हो रही है। उन्होंने आगे कहा, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी के आशीर्वाद और आप सभी लोगों के प्रेम व समर्थन से मुझे ताकत मिली। आप सभी ने मुझे मां की ममता दी, और मेरी

ताकत बनकर हमेशा साथ खड़े रहे। इसी से मुझे लोगों को न्याय दिलाने और सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलती रही।

उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कभी भी आत्मसम्मान नहीं छोड़ा, और गन्ना तोड़ मजदूरों के हक और न्याय के लिए हमेशा प्रयासशील रही हैं। मेहनत, परिश्रम और आत्मसम्मान - इन तीन सिद्धांतों पर ही हमारा समाज हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, ऐसा दृढ़ विश्वास उन्होंने व्यक्त किया। पंकजा मुंडे ने यह भी कहा कि भगवान बाबा प्रतिष्ठान के माध्यम से एक संस्कारी पीढ़ी का निर्माण होना चाहिए और इस प्रतिष्ठान के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण व भूमिपूजन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, यह मेरे लिए गर्व की बात है।

आ. संदीप क्षीरसागर के दूरदर्शी प्रयास को सफलता

बिंदुसरा नदी पर पुल कम बंधारे के कार्य का शुभारंभ आ. क्षीरसागर के हाथों



बीड, ३ अप्रैल (प्रतिनिधि): बीड शहर की बिंदुसरा नदी में पुल कम बंधारे के निर्माण कार्य की आखिरकार शुरुआत हो गई है। गुरुवार (दिनांक ३ अप्रैल) को इस कार्य का शुभारंभ बीड के विधायक आ. संदीप क्षीरसागर के हाथों संपन्न हुआ। आ. क्षीरसागर इस योजना के लिए पिछले कई वर्षों से लगातार प्रयासरत थे। अब जब इस कार्य का इफतेतह हो चुका है, तो जल्द ही इसका निर्माण पूर्ण होने की उम्मीद है।

इस पुल कम कोल्हापुरी शैली के बंधारे के माध्यम से बीड शहर और आसपास के गांवों में भूजल स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह निश्चित ही क्षेत्र के लिए एक सुखद और

लाभदायक पहल है।

बाशीं नाका क्षेत्र के समीप बिंदुसरा नदी के पात्र में यह बंधारा निर्मित किया जा रहा है, जिससे नदी का बहता पानी रोका जा सके। इस कार्य को अमल में लाने के लिए आ. संदीप क्षीरसागर ने लगातार कई वर्षों तक शासन और प्रशासन से इस विषय पर जोरदार और नियमित तौर पर अनुवर्तन किया। अंततः उनके अथक प्रयासों को सफलता मिली है।

बिंदुसरा नदी पर निर्मित हो रहा यह बंधारा बीड जिले में सिंचाई और पेयजल आपूर्ति के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। यह परियोजना बीडवासियों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होने वाली है।

पुल कम बंधारा-सिंचाई और जल संग्रहण में बड़ी मदद

शुभारंभित बिंदुसरा नदी पर कोल्हापुरी शैली में बन रहा पुल कम बंधारा बीड शहर तथा लगभग ५ किलोमीटर के दायरे में स्थित गांवों की भूजल स्तर में बढ़ोतरी करेगा। बीड जिले में वर्षा की अनियमितता के कारण प्रत्येक गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत महसूस की जाती है। लेकिन इस बंधारे के निर्माण से जल संग्रहण की सुविधा विकसित होगी। जिससे पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और किसानों को सिंचाई के लिए पानी प्राप्त होगा। बिंदुसरा नदी पर यह बंधारा कम पुल एक दूरदर्शी योजना थी, जिसे आ. संदीप क्षीरसागर ने शुरू से ही अपने दृष्टिकोण में रखते हुए साकार किया। उन्होंने शासन स्तर पर निरंतर प्रयास किए और विधानसभा में कई बार यह मुद्दा उठाया। अंततः अब उनके प्रयासों को सफलता मिली है और यह परियोजना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। इस इफतेतह के मौके पर पूर्व विधायक सय्यद सलीम भी साथ थे।

वक्फ संशोधन विधेयक २०२४ को देशभर के उलेमा व मशाइख ने किया खारिज



नवी दिल्ली: संवादाता

देशभर में चर्चा का विषय बने वक्फ संशोधन विधेयक २०२४ को संसद में पारित किए जाने के बाद अब राज्यसभा से पास होने की संभावना है, क्योंकि दोनों सदनों में बहुमत उन्हीं पार्टियों को प्राप्त है, जिन्हें मुस्लिम विरोधी माना जाता है। लोकसभा में लगभग १२ घंटे लंबी बहस के बाद देर रात करीब २ बजे यह विधेयक पारित कर दिया गया, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय में कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। विशेष रूप से उलेमा और मशाइख इस विधेयक के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और अब संवैधानिक दायरे में रहते हुए शांतिपूर्ण संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं।

मुंबई में उलेमा की आपात बैठक विधेयक के पारित होने के बाद, मुंबई की हांडी वाली मस्जिद में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलेमा और रज़ा एकेडमी की अगुवाई में एक आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक में बड़ी संख्या में उलेमा, मस्जिदों के इमाम और मदरसों के शिक्षक शामिल हुए और इस कानून के प्रति गहरा आक्रोश व्यक्त किया। रज़ा एकेडमी के प्रमुख हाजी मोहम्मद सईद नूरी का बयान

बैठक की अध्यक्षता करते हुए रज़ा एकेडमी के प्रमुख हाजी मोहम्मद सईद नूरी साहब ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक का पारित होना न केवल भारत के मुसलमानों बल्कि संविधान में विश्वास रखने वाले सभी नागरिकों के लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि इस कानून के जरिए दो समुदायों के बीच नफरत पैदा करने की साजिश रची जा रही है।

उन्होंने आगे कहा, वक्फ संपत्तियों पर केवल मुसलमानों का अधिकार है, कोई दूसरा इस पर कब्ज़ा नहीं कर सकता। यह कानून एकतरफा तरीके से मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनने का प्रयास है और दूसरी तरफ एक खास वर्ग को खुश करने के लिए वोट बैंक की राजनीति हो रही है। लेकिन अब यह लड़ाई संविधान के दायरे में रहकर सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जाएगी। हम किसी भी कीमत पर चुप नहीं बैठेंगे।

मस्जिदों के इमामों से अपील हाजी सईद नूरी ने सभी मस्जिदों के इमामों और उलेमा से अपील की कि वे

जुमे के खुतबे में वक्फ की शरई हैसियत और उसके महत्व पर रोशनी डालें, ताकि आम जनता को भी वक्फ की संपत्तियों की अहमियत समझाई जा सके। अन्य उलेमा के तीखे बयान मौलाना एजाज़ अहमद कश्मीरी ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा, बीजेपी सरकार ने सोची-समझी साजिश के तहत यह विधेयक मुसलमानों पर थोपा है, ताकि वक्फ की जमीनों पर आसानी से कब्ज़ा किया जा सके। गृह मंत्री अमित शाह ने जिस ढिठाई से कहा कि यह कानून सभी को मानना होगा, हम उन्हें साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि जबरदस्ती थोपा गया कानून हमें मंजूर नहीं है।

उन्होंने आगे कहा, अगर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल किया जा सकता है, तो क्या राम मंदिर और अन्य हिंदू मंदिरों में किसी मुसलमान को चेयरमैन बनाया जाएगा? अगर यह संभव नहीं है, तो फिर मुस्लिम धार्मिक मामलों में दखलअंदाजी क्यों हो रही है?

मौलाना अमानुल्लाह रज़ा खान ने कहा, केंद्र सरकार हर मोर्चे पर मुसलमानों को परेशान कर रही है। पहले तीन तलाक, फिर उ-उ-उ और अब वक्फ की जमीनों पर कब्ज़े का कानून। खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बिल के नाम पर गुमराह किया जा रहा है, जो बेहद निंदनीय और सोची-समझी साजिश है।

मौलाना खलीलुर्हमान नूरी ने कहा कि,

आज बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भले ही उसके साथ हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब बीजेपी खुद ही इन पार्टियों को निगल जाएगी, जिसका अंदाजा शायद अभी नितीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को नहीं है।

मौलाना मोहम्मद अब्बास रिज़वी ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा,

वक्फ संशोधन विधेयक को उम्मीद की 'किरण' कहा जा रहा है, लेकिन यह 'किरण' केवल रिजिजू के लिए है, बाकी मुसलमानों के लिए तो अंधेरा ही अंधेरा है।

सख्त विरोध और चेतावनी मौलाना ज़फ़रुद्दीन रिज़वी ने कहा कि अब मुसलमानों को डरकर नहीं, बल्कि डटकर संविधान के तहत अपने हक के लिए मैदान में उतरना होगा।

मौलाना अज़मत अलीमी और मौलाना जहांगीर कादरी ने संयुक्त रूप से कहा कि

वक्फ संशोधन विधेयक २०२४ किसी भी हाल में हमें मंजूर नहीं है।

सामाजिक कार्यकर्ता इरफान डियोटे की टिप्पणी

सामाजिक कार्यकर्ता इरफान डियोटे ने कहा कि जो पार्टियां मुस्लिम वोटों से सालों तक सत्ता में बनी रहीं, उनका असली चेहरा अब सामने आ गया है। मुसलमानों को इन्हें सही तरीके से पहचान लेना चाहिए।

बैठक में मौजूद प्रमुख उलेमा और गणमान्य व्यक्ति इस आपात बैठक में सैक.

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

स्कूलों की सभी भौतिक सुविधाओं के साथ किया जाए ‘जियो टैगिंग’ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सभी सरकारी इमारतों का हो सौर ऊर्जिकरण, २२ विभागों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के निर्देश

मुंबई, ४ अप्रैल (विशेष प्रतिनिधि): राज्य के सभी विभागों की स्कूलों में उपलब्ध पीने के पानी, शौचालय और अन्य भौतिक सुविधाओं के साथ 'जियो टैगिंग' की जाए। नामांकित स्कूलों की वर्तमान स्थिति की जांच विभाग स्तर पर की जाए। साथ ही, जिला नियोजन निधि का उपयोग करने वाले प्रत्येक सरकारी कार्यालय की इमारत का सौर ऊर्जिकरण किया जाए। ये निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को सह्याद्री अतिथिगृह में आयोजित समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने २२ विभागों के १०० दिनी कार्यक्रम की समीक्षा की। इस दौरान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, विभागीय मंत्री, राज्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव, प्रधान



सचिव, सचिव और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सभी सरकारी इमारतों पर लगाए जाने वाले सौर ऊर्जा पैनलों का अगले पांच वर्षों तक प्रबंधन संबंधित आपूर्ति कंपनी को सौंपा जाए। पैनलों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। सरकार ७.५ अश्वशक्ति तक की क्षमता वाले सौर

ऊर्जा पंपों पर अनुदान दे रही है। जहां बूस्टर पंप की आवश्यकता हो, वहां वह भी उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षा, सड़क और सुरक्षा पर विशेष जोर मुख्यमंत्री ने शिक्षा का अधिकार (ठडए) अधिनियम में संशोधन की बात करते हुए कहा कि निर्धारित दूरी के भीतर प्रवेश के लिए सबसे पहले

सरकारी स्कूलों को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही राज्य में सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एकीकृत परिवहन प्रबंधन प्रणाली (खडचड) को लागू किया जाए, ताकि यातायात नियमों के उल्लंघन को रोका जा सके और दुर्घटनाओं वाले स्थानों में सुधार किया जा सके। इसके लिए 'ई-टीडीआर' नामक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म शुरू करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि १०० दिनी कार्यक्रम के तहत विभागों ने हरे और पीले रंग के चिन्हित बिंदुओं पर सराहनीय कार्य किया है। अब १ मई तक लाल रंग वाले अपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर कार्यों को पूरा किया जाए। इसके साथ ही, प्रत्येक विभाग को अपनी वेबसाइट पर १०० दिनी कार्यक्रम के तहत किए गए, पूर्ण किए

गए और अपूर्ण कार्यों की जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध करानी चाहिए। डड महामंडल के लिए अलग विज्ञापन नीति की जरूरत - उपमुख्यमंत्री शिंदे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य परिवहन (डड) महामंडल को अपनी अलग विज्ञापन नीति तैयार करनी चाहिए और इसके लिए एक अच्छे सलाहकार की नियुक्ति की जाए जिससे महामंडल की आय में वृद्धि हो सके। बैठक में २२ विभागों के कुल मुद्दों की समीक्षा की गई। इनमें से ४४% मुद्दों पर कार्य पूर्ण हो चुका है, ३७% कार्य अंतिम चरण में हैं और समय पर पूरे हो जाएंगे, जबकि शेष १९% कार्य अभी तक अपूर्ण हैं। इन अपूर्ण कार्यों को लेकर संबंधित विभागों ने अपनी समस्याएं सामने रखीं।

जन सुरक्षा कानून के विरोध में पत्रकार संगठनों का तीव्र प्रदर्शन



मुंबई, ४ अप्रैल (विशेष प्रतिनिधि): महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नए अभिव्यक्ति स्वतंत्रता कानून के विरोध में राज्यभर के पत्रकार संगठनों ने कड़ा विरोध जताते हुए मुंबई मराठी पत्रकार संघ में पत्रकार अभिव्यक्ति संरक्षण मंच के माध्यम से जोरदार प्रदर्शन किया। पत्रकारों ने आरोप लगाया कि यह कानून मीडिया की स्वतंत्रता को बाधित करने वाला है और इसे अविलंब वापस लिया जाना चाहिए। अन्यथा आंदोलन और भी उग्र किया जाएगा, ऐसी चेतावनी पत्रकार संगठनों ने दी है। आजाद मैदान के पास स्थित पत्रकार संघ के प्रांगण से रैली निकालकर पत्रकारों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी बात रखी। इस विरोध प्रदर्शन में मुंबई मराठी पत्रकार संघ, मराठी पत्रकार परिषद, मुंबई प्रेस क्लब, मंत्रालय व विधानमंडल वार्ताहर संघ, टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन, पुणे श्रमिक पत्रकार संघ, बृहन्मुंबई यूनिन ऑफ जर्नलिस्ट, मुंबई क्राइम रिपोर्ट एसोसिएशन, मुंबई हिंदी पत्रकार संघ सहित कई पत्रकार संगठनों के प्रमुख, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए। मुंबई मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष संदीप चव्हाण ने कहा, सरकार की यह मनमानी हमें स्वीकार नहीं। पत्रकारों की स्वतंत्रता का गला घोटने का कोई भी प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एम. देशमुख ने कहा, जैसे हमने पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए आंदोलन किया, वैसे ही अब भी आंदोलन को मजबूर न करें। वरिष्ठ पत्रकार महेश म्हात्रे ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, यह आंदोलन एक चिंगारी है जो कभी भी भड़क सकता है। सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार किरण नाइक ने कहा, अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। वहां वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सापटे ने कहा, यह विधेयक पत्रकार विरोधी है, इसलिए इसका तीव्र विरोध आवश्यक है। प्रदर्शन में पत्रकारों ने एक स्वर में यह मांग की कि सरकार को यह प्रस्तावित कानून तुरंत वापस लेना चाहिए, अन्यथा पत्रकार वर्ग राज्यव्यापी आंदोलन करेगा।

भक्तों की जीप मांजरसुंबा घाट में दुर्घटनाग्रस्त

१४ गंभीर रूप से घायल, ४ को मामूली चोटें

बीड, ३ अप्रैल (प्रतिनिधि): बीड-मांजरसुंबा मार्ग पर मांजरसुंबा घाट के पास मंगलवार देर रात लगभग २ बजे एक क्रूजर जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह जीप जालना से तुळजापूर दर्शन के लिए जा रही थी। दुर्घटना में १४ यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि ४ अन्य को मामूली चोटें आई हैं। सभी घायलों का इलाज बीड के जिला अस्पताल में किया गया। जानकारी के अनुसार, जालना शहर से भक्तों का एक समूह कुल १८ यात्रियों के साथ क्रूजर जीप से तुळजापूर दर्शन के लिए निकला था। बीड शहर पार कर धुळे-सोलापुर महामार्ग पर आगे बढ़ते समय चालक का नियंत्रण गंदाई से हट गया, जिससे जीप सीधे डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। दुर्घटना के तुरंत बाद अन्य यात्रियों और राहगीरों ने घायलों की मदद की और सभी को बीड जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक साथ १४ घायलों के पहुंचने से अस्पताल में डॉक्टरों और कर्मचारियों के बीच अफरा-तफरी मच गई, लेकिन सभी का तत्परता से इलाज किया गया। डॉक्टरों के अनुसार अधिकांश घायलों को सिर में चोटें आई हैं, जिनमें कुछ को १४ टंके भी लगे हैं। हालांकि सीमांश्वर्य किसी को भी मस्तिष्क में गंभीर चोट नहीं लगी है और सभी की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही घायलों के परिजन बीड पहुंच गए और प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को आगे के इलाज के लिए जालना ले जाया गया। फिलहाल घायलों के नाम और जीप का नंबर स्पष्ट नहीं हो सका है।

अजित दादा पवार हैं संवेदनहीन पालक मंत्री: एमआईएम के शफीक भाऊ की तीव्र आलोचना

बीड, ४ अप्रैल (प्रतिनिधि): महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और बीड जिले के पालक मंत्री अजित दादा पवार के बीड दौरे के बाद, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इस्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) के बीड जिला अध्यक्ष डॉ. शेख शफीक भाऊ ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं।



शफीक भाऊ ने कहा कि बीड जिले के गेवराई तालुका स्थित अर्धामसला गांव में मस्जिद में हुए धमाके जैसी आतंकी घटना को लेकर अजित दादा पवार ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। सरकारक मंत्री होने के नाते उन्हें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति की जानकारी लेनी चाहिए थी और समाज में सख्त संदेश देने के लिए आरोपियों के

खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश देने चाहिए थे। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि अजित दादा पवार को बीड शहर में मुस्लिम नेताओं के घर जाकर शोरखुरा पीने का समय मिल गया, लेकिन अर्धामसला जाकर पीड़ितों से मिलने और घटना का जायजा लेने का समय नहीं मिल पाया - यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। शफीक भाऊ ने आगे कहा कि एक जिम्मेदार नेता से संवेदनशीलता की अपेक्षा होती है, लेकिन अजित दादा पवार के व्यवहार में ऐसी कोई संवेदनशीलता नहीं दिखी। इसी कारण से हम उन्हें संवेदनहीन पालक मंत्री कह रहे हैं, उन्होंने इस तरह तीखी प्रतिक्रिया दी।

स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव में शिवसेना का भगवा लहराने के लिए पूरी ताकत से काम में जुट जाएं-बापूसाहेब मोरे

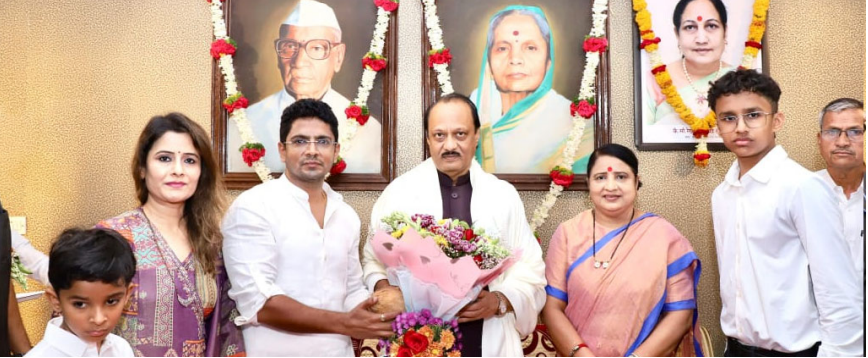
बीड, ३ अप्रैल (प्रतिनिधि): पिछले कुछ वर्षों से लंबित चल रही स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव अब विधानसभा चुनाव के बाद शीघ्र ही घोषित होने वाले हैं। राज्य में शिवसेना को मिले व्यापक जनसमर्थन के बाद अब बीड जिले की स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव में भी शिवसेना का भगवा लहराना है। इसके लिए शिवसैनिकों को पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरना होगा। अधिक से अधिक सदस्यता फॉर्म भरकर पार्टी संगठन को मजबूत करने का आह्वान शिवसेना बीड जिला संपर्क प्रमुख बापूसाहेब मोरे ने किया। यह आवाहन उन्होंने ३ अप्रैल २०२५ को दोपहर १२ बजे बीड के माळीवेस चौक स्थित हनुमान मंदिर सभागृह में आयोजित शिवसेना बीड जिला समीक्षा बैठक एवं सदस्यता अभियान के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए किया।



यह बैठक शिवसेना के मुख्य नेता एवं उपमुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे, सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे, शिवसेना सचिव संजय मोरे, उपनेता एवं मराठवाड़ा संपर्क प्रमुख अर्जुन खोतकर, तथा विभागीय सचिव अशोक पटवर्धन के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। इस दौरान जिला संपर्क प्रमुख बापूसाहेब मोरे, जिलाध्यक्ष अनिलदादा जगताप, सचिन मुळुक, स्वप्नील गलहर आदि प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में पूर्व सदस्यता अभियान की समीक्षा की गई और नये सदस्यता अभियान का विधिवत शुभारंभ शिवसेना, महिला आघाड़ी, युवासेना, शेतकरी सेना, ओबीसी सेना, अनुसूचित जाति-जनजाति सेना के पूर्व एवं वर्तमान

पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, शाखा प्रमुखों एवं शिवसैनिकों के हाथों किया गया। जिलाध्यक्ष अनिलदादा जगताप और सचिन मुळुक ने अपने भाषण में कहा कि बीड जिले से अधिकतम सदस्यता फॉर्म भरकर एकनाथ शिंदे साहेब की ताकत को और मजबूत बनाना तथा आगामी स्थानीय स्वराज्य चुनावों में शिवसेना का भगवा लहराना, यह जिम्मेदारी आजी-माजी पदाधिकारी, शाखा प्रमुख और शिवसैनिकों की है। सभी को इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। बैठक का संचालन प्रतीक कांबळे ने किया और आभार प्रदर्शन उपजिलाध्यक्ष संतोष जाधव ने किया।

बीड: एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार ने डॉ.योगेश क्षीरसागर के निवास पर दी सददिच्छा भेंट



बीड, २ अप्रैल: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बीड जिले के संपर्क मंत्री अजितदादा पवार ने युवा नेता डॉ. योगेश क्षीरसागर के निवास स्थान पर सददिच्छा भेंट दी। इस अवसर पर डॉ.

योगेश क्षीरसागर का सम्मान भी किया गया। सम्मान समारोह में डॉ. दीपा क्षीरसागर, डॉ. सारिका क्षीरसागर सहित पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।

बिजली बिल सस्ता करने का वादा साबित हुआ छलावा-अतुल लोंढे

मुंबई, ३ अप्रैल (प्रतिनिधि): महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने भाजपा-युती सरकार पर आम जनता के साथ गंभीर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा १ अप्रैल २०२५ से बिजली बिल सस्ता करने का किया गया ऐलान सिर्फ एक दिखावा साबित हुआ है। आम नागरिकों को बिजली बिल में कोई राहत नहीं मिली, बल्कि उन्हें भारी बिलों का झटका सहना पड़ रहा है। अतुल लोंढे ने कहा कि पहले 'लाडकी बहन' योजना में २१०० रुपये देने के वादे को लेकर सरकार ने टालमटोल की नीति अपनाई, फिर किसानों को कर्जमाफी देने में नाकाम

आम नागरिकों को नहीं मिली कोई राहत, बीजेपी-युती सरकार ने फिर किया धोखा

रही और अब बिजली उपभोक्ताओं को भी छलने का काम किया गया है। बिजली कंपनियों की स्थिति और सरकार का झूठा दावा लोंढे ने बताया कि महाराष्ट्र में बिजली क्षेत्र की तीन प्रमुख कंपनियां - 'महानिर्मिती', 'महापारेण' और 'महावितरण' - राज्य सरकार के अधीन हैं। बिजली बिल से जुड़ी दरों का प्रस्ताव बिजली नियामक आयोग (चाएड) के पास भेजा जाता है, और अंतिम निर्णय वही करता

है। २८ मार्च को मुख्यमंत्री फडणवीस ने घोषणा की थी कि १ अप्रैल २०२५ से अगले पांच वर्षों तक बिजली दरों पर चरणबद्ध तरीके से कम की जाएंगी। इसी दिन बिजली नियामक आयोग ने भी १०% बिजली दरों में कटौती की घोषणा की थी। लेकिन राज्य सरकार की कंपनी 'महावितरण' ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कंपनी पर ९० हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है, और अगर बिजली दरें

घटाई गई तो कंपनी को भारी नुकसान होगा। क्या मुख्यमंत्री को अपने ही विभाग की स्थिति का अंदाजा नहीं था? लोंढे ने सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री फडणवीस को अपने ही विभाग की आर्थिक स्थिति की जानकारी नहीं थी? या फिर बिजली नियामक आयोग ने अपने स्तर पर ही यह फैसला लिया? उन्होंने कहा कि यह सब जनता के साथ धोखा है।

अतुल लोंढे ने कहा कि विधानसभा चुनावों में भाजपा ने किसानों को कर्जमाफी, 'लाडकी बहन' योजना की राशि १५०० से बढ़ाकर २१०० रुपये करने और २.५ लाख सरकारी पदों पर भर्ती जैसे वादे किए थे। लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार का रुख पूरी तरह बदल गया है। किसानों, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को धोखा देने के बाद अब आम बिजली उपभोक्ताओं को भी जबरदस्ती आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है। जनता के पास अब सिर्फ भारी-भरकम बिजली बिल चुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, लोंढे ने ऐसा कहते हुए सरकार पर तीखा प्रहार किया।

परशुराम संस्कार सेवा संघ द्वारा सामूहिक उपनयन संस्कार समारोह सम्पन्न

बीड, २ अप्रैल (प्रतिनिधि): परशुराम संस्कार सेवा संघ महाराष्ट्र राज्य, बीड की ओर से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला सामूहिक उपनयन संस्कार समारोह इस वर्ष भी भव्य रूप में संपन्न हुआ। बुधवार, २ अप्रैल २०२५ को अभिजीत मुहूर्त (प्रातः १०:५४ बजे) पर यह आयोजन साईं पंढरी मंगल कार्यालय, अंकुश नगर, बीड में बड़े धूमधाम से आयोजित किया गया। इस उपनयन संस्कार समारोह में कुल १२ बटुओं का सामूहिक मुंज विधिवत रूप से संपन्न कराया गया। इस अवसर पर प्रमुख

अतिथि के रूप में परशुराम आर्थिक विकास महामंडल के अध्यक्ष श्री आशिषजी दामले उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत प्रमुख अतिथियों के स्वागत से हुई। पुरुष मान्यवरों का स्वागत परशुराम संस्कार सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष गजानन राव जोशी, प्रदेश अध्यक्ष बालासाहेब ठिगळे, प्रदेश सचिव संजय कुलकर्णी, प्रदेश संपर्क प्रमुख बाबा पाटक और जिलाध्यक्ष मुकुंद खडकीकर ने किया। वहीं महिला अतिथियों का स्वागत सौ. मंगल ताई आगवान, सौ. अमृता जोशी, सौ. अर्चना जोशी और सौ. सुषमा ताई

१२ बटुओं का विधिवत मुंज आयोजन, प्रमुख अतिथि आशिष दामले रहे उपस्थित



ठिगळे द्वारा किया गया। बटुओं को महंत अमृत महाराज जोशी द्वारा आशीर्वाद प्रदान किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के रूप में एंड.

कालिदास नाना ठिगळे, शिवसेना जिलाध्यक्ष अनिल दादा जगताप, हेमंत भैर्या क्षीरसागर, लोकांक्षा के संपादक प्रशांत सुलाखे, एकनाथ महाराज पुजारी, लोकप्रख के संपादक दिलीप खिस्ती, पूर्व नगरसेवक किशोर काळे, राजेंद्र काळे, परशुराम गुरुकुंदे, चंद्रकांत नाना मुळे, ब्राह्मण महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष निखिल लातूरकर, प्रदेश सचिव संजय सुपेकर, अभिजित बरिदे, बीड जिल्हा भाजपा अध्यक्ष शंकर देशमुख, श्रीमती प्रज्ञाताई रामदासी, सौ. सारिकाताई क्षीरसागर और संतोषराव लहाने आदि मान्यवर उपस्थित थे। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए

परशुराम संस्कार सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष गजाननराव जोशी, प्रदेश अध्यक्ष बालासाहेब ठिगळे, प्रदेश सचिव संजय कुलकर्णी, प्रदेश संपर्क प्रमुख बाबा पाटक, मराठवाड़ा अध्यक्ष विनायक देशमुख, जिलाध्यक्ष मुकुंद खडकीकर, विनोद राव रामदासी, भास्कर मुळे, रविंद्र कुलकर्णी, महेंद्र कुलकर्णी, शशिकांत पाटील, महिला मार्गदर्शक सौ. मंगल ताई आगवान, महिला जिलाध्यक्ष सौ. अर्चना ताई जोशी, महिला प्रदेश सचिव सौ. अमृता जोशी, सौ. सुषमा ताई ठिगळे, सौ. वर्षा देशमुख और अन्य कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किए।